PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 010
दि. 10.05.2026, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल में मिथुन ने कैसे निभाया भाजपा की जीत में अहम रोल, सुवेंदु के शपथ वाले मंच पर क्या हुई पीएम मोदी से बात?

आज पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली. इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसपर सभी ने गौर किया. पर्दे के पीछे से मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ कई ऐसे रोल निभाए, जिसने बीजेपी को जीतने मदद की.

''नई सरकार में मंत्री पद का अवसर कई नेता तलाश रहे होंगे, लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे एक ऐसे नेता का जिक्र भी आज जरूरी है. जिसने अवसर से ज्यादा पार्टी के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी और आज मंच पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस संघर्ष को सराहा. शपथ ग्रहण समारोह में एक और ऐसी तस्वीर थी, जिसका जिक्र करना आज जरूरी है.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के मंच पर मौजूद, अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती के पास खुद चलकर गए. उनसे बातें कीं. इस मुलाकात को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, ये कमिटमेंट और संघर्ष का सम्मान था.

बीजेपी की जीत में मिथुन ने निभाया अहम रोल

पर्दे के पीछे से मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की जीत के लिए क्या रोल निभाया आपको ये जानना चाहिए. मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन उस वक्त थामा, जब टॉलीवुड में बीजेपी का खुलकर समर्थन करना तो दूर नाम लेना तक गुनाह माना जाता था. बीजेपी के करीब जाते ही कलाकारों को फिल्मों से निकाल दिया जाता था. शो कैंसिल कर दिए जाते थे. इंडस्ट्री में बॉयकॉट कर दिया जाता था. 7 मार्च 2021 को मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन किया और पांच सालों तक पार्टी का जमकर प्रचार किया.

जब मिथुन की रैलियों में उमड़ी भीड़

उनकी लोकप्रियता कोलकाता के एलीट क्लास से लेकर सुंदरबन के मछुआरों और पुरुलिया के आदिवासियों तक है. उन्होंने बीजेपी के लिए वो 'इमोशनल कनेक्ट' पैदा किया जिसकी कमी पहले खटकती थी. उन्होंने सिर्फ हिंदू वोटों की बात नहीं की, बल्कि 'गरीब और शोषित' बंगाली की बात की. उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ ने ये साबित किया कि बीजेपी अब बंगाल के लिए 'बाहरी' पार्टी नहीं रही.

मिथुन चक्रवर्ती ने बिना किसी बड़े पद की लालसा के बंगाल में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखी और आज मंच पर प्रधानमंत्री जिस तरह उनसे खुद मिलने आए. उससे ये साबित हो गया कि बंगाल की राजनीति में मिथुन चक्रवर्ती का कद बहुत बड़ा है.

प्रधानमंत्री 10-11 मई को गुजरात का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे

''प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10-11 मई, 2026 को गुजरात का दौरा करेंगे। वे 10 मई की रात को जामनगर, गुजरात पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 11 मई को सुबह लगभग 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री वडोदरा के लिए रवाना होंगे, जहां वे शाम लगभग 6 बजे सरदारधाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। वे दोनों अवसरों पर जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे।

प्रधानमंत्री सोमनाथ में

प्रधानमंत्री भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत की अटूट आस्था और सभ्यतागत विरासत के प्रतीक पवित्र सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।

समारोहों के भाग के रूप में, प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे विशेष महा पूजा, जिसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। ये मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण के प्रतीक हैं।

प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे।

प्रधानमंत्री वडोदरा में, प्रधानमंत्री वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा के साथ-साथ केंद्रीय भोजन कक्ष, पुस्तकालय और सभागार जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री सरदारधाम परिसर में स्वागत क्षेत्र, नागरिक सुविधाएं, भोजन क्षेत्र और ई-पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे।

पीएम ने श्री सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सुवेंदु अधिकारी को आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सुवेंदु अधिकारी ने जनता से गहरे जुड़ाव रखने वाले और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। श्री मोदी ने उन्हें आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने पर श्री दिलीप घोष, श्रीमती अग्निमित्रा पॉल, श्री अशोक कीर्तनिया, श्री क्षुदिराम टुडू और श्री निसीथ प्रमाणिक को भी बधाई दी।

श्री मोदी ने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री बनने पर वे पश्चिम बंगाल के विकास पथ को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा; 'श्री सुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहकर और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझते हुए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनके सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।

'पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर दिलीप घोष जी, अग्निमित्रा पॉल जी, अशोक कीर्तनिया जी, क्षुदिराम टुडू जी और निसीथ प्रमाणिक जी को हार्दिक बधाई।

इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुझे विश्वास है कि मंत्री के रूप में वे पश्चिम बंगाल के विकास पथ को आगे बढ़ाएंगे। मेरी शुभकामनाएं।

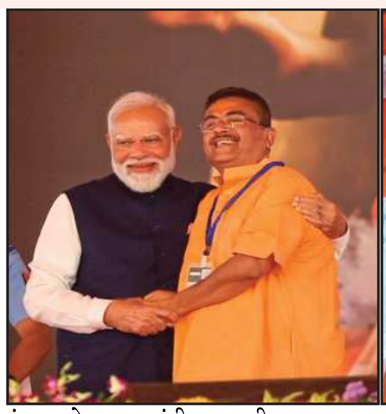

यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, 50 हजार करोड़ की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास

(जीएनएस)।

लखनऊ। बंगाल चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा का राजनीतिक केंद्र बिंदु अब उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। राज्य में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जहां भाजपा संगठन जमीनी स्तर पर काम करने में जुटा है।

वहीं प्रदेश सरकार बड़ी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। सरकार अब लगातार बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से जनता के बीच अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाएगी। विभागों से लोकार्पण व शिलान्यास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं का ब्योरा मांगा गया है।

विभागों की रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम होगा। लोकार्पण व शिलान्यास के समस्त कार्यक्रम दिसंबर से पहले ही किए जाएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री शामिल होंगे।

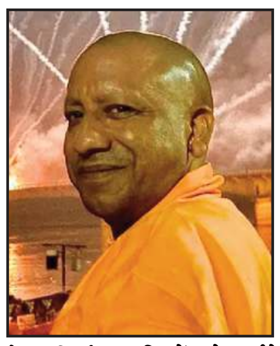

कुछ बड़ी परियोजनाओं में प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। अकेले लोक निर्माण विभाग ने ही 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और 18 परियोजनाओं के शिलान्यास की सूची तैयार की है। इन परियोजनाओं की लागत 9720 करोड़ रुपये है। ये सभी परियोजनाएं सड़कों व सेतुओं के निर्माण से संबंधित हैं।

दो हाईवे कॉरिडोर के शिलान्यास की तैयारी

विभाग पूर्वांचल में उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले दो हाईवे कॉरिडोर के शिलान्यास की तैयारी कर रहा है। ये हाईवे पूर्वांचल के दर्जन भर जिलों को हाईवे नेटवर्क से आपस में जोड़ेंगे। इन दोनों कॉरिडोर से पिछले चुनाव में जहां भाजपा के खराब प्रदर्शन वाले जिले गाजीपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर आदि जुड़ रहे हैं। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह के मुताबिक फरुर्खाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कराने की तैयारी चल रही है। लखनऊ में विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर तथा नाइट सफारी का शिलान्यास भी होगा। वहीं, मेरठ में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का लोकार्पण होगा। जानकार बताते हैं कि इन लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से सरकार प्रदेश के हर हिस्से को संदेश देने का काम करेगी, क्योंकि इन लिंक एक्सप्रेसवे से प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब और दक्षिण तक के कई जिले सीधे जुड़ रहे हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने रवांडा की यात्रा करने में असमर्थता पर खेद व्यक्त कि, लेकिन वर्चुअल माध्यम से शामिल होने के लिए सहमत हुए

भारत में रवांडा की उच्चायुक्त सुश्री जैकलीन मुकांगिरा ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को रवांडा के राष्ट्रपति का 'अफ्रीका के लिए परमाणु ऊर्जा नवाचार शिखर सम्मेलन' में शामिल होने का निमंत्रण दिया

भारत और रवांडा परमाणु ऊर्जा, एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर चर्चा की

(जीएनएस)।

भारत में रवांडा की उच्चायुक्त सुश्री जैकलीन मुकांगिरा ने आज केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उन्हें किगाली रवांडा में 18 से 21 मई 2026 तक आयोजित होने वाले 'अफ्रीका के लिए परमाणु ऊर्जा नवाचार शिखर सम्मेलन' (एनईआईएसए 2026) में शमिल होने के लिए निमंत्रण दिया।

हालांकि डॉ. जितेंद्र सिंह ने रवांडा का दौरा करने में असमर्थता पर खेद व्यक्त किया, लेकिन शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शमिल होने और निर्दिष्ट सत्र को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की।

रवांडा सरकार की ओर से यह निमंत्रण दिया गया था। इसमें रवांडा की आईसीटी और नवाचार मंत्री माननीय पाउला इंगाबियर भी शामिल थीं। एन ई आई एस ए 2026 का आयोजन किगाली कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए), अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीए), परमाणु ऊर्जा एजेंसी, विश्व परमाणु संघ और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा नवाचार, एआई एकीकरण, विनिर्माण इकोसिस्टम और अफ्रीका के लिए भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा साझेदारी पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रियों, नीति निमार्ताओं, वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों, उद्योग जगत के प्रमुखों और रणनीतिक हितधारकों को एक साथ आने की उम्मीद है।

स्वस्थ होकर लौटे अजय राय, मुख्यालय में हुआ स्वागत

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय स्वस्थ होकर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस

मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं व कार्यकताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं व कार्यकताओं से संगठन की गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। इससे पहले उन्होंने हजरतगंज के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में पूजा की।

लखनऊ पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

लखनऊ। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शनिवार को लखनऊ पहुंचे। उनका लखनऊ आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद संजय सेठ के आवास पर भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका अभिनंदन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उपराज्यपाल का स्वागत किया। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। महापौर सुषमा खर्कवाल और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उपराज्यपाल का स्वागत किया।

सीएम बनते ही एक्शन में आए शुभेंदु अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात की समीक्षा की, सोमवार को करेंगे बड़ी मीटिंग

शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसके साथ ही उन्होंने फौरी तौर पर कानून-व्यवस्था के हालात की समीक्षा की। वे इस संबंध में सोमवार को एक बड़ी मीटिंग करनेवाले हैं।

(जीएनएस)।

कोलकाताः मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। पार्टी के घोषणा पत्र के मुताबिक जनता से किए गए वादों को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में कानून-व्यवस्था का मुद्दा काफी अहम है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला, पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार, बैठक में कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद भी उपस्थित थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के संचालन के बारे में भी जानकारी ली और मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि योजनाएं बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी रहें।

सम्पादकीय

खाड़ी देशों के पीछे पड़ा ईरान

अमेरिका और इजरायल के साथ जंग के दौरान ईरान की जवाबी कार्रवाई पारंपरिक लक्ष्यों से आगे बढ़ गई, उसने खाड़ी देशों में लगातार हमले किए और यह सिलसिला अभी भी जारी है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने दावा किया है कि ईरान ने उस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका। फुजैरा में एक तेल फैसिलिटी पर बहरहाल एक ड्रोन गिरने से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय घायल हो गए। इससे पहले भी टैंकर पर ड्रोन हमले की घटना सामने आई थी। ईरान-अमेरिका के बीच सीजफायर के बाद यह इस तरह का पहला हमला है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार शाम बताया कि देश के अलग- अलग हिस्सों में बैलिस्टिक मिसाल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका से जुड़े डिजिटल हब, क्लाउड, इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेटा केंद्रों को निशाना बनाकर जंग के दायरे को और फैला दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि उसने यूएई और बहरीन में डेटा हब्स पर ड्रोन हमले किए। यह आज के जंग में एक अभूतपूर्व कारण है, जिसमें सिर्फ साइबर घुसपैठ की बजाए आम लोगों से जुड़ें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सोची-समझी रणनीति के तहत हमले किए गए हैं? ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि इसका मकसद इन डेटा सेंटरों की दुश्मन की सैन्य और अन्य गतिविधियों में मदद करने वाली भूमिका को सामने लाना और उसे रोकना है। मौजूदा दौर में क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर अब दोहरे इस्तेमाल वाली रणनीतिक ढांचे के तौर पर उभरा है। यह बैंकिग एविएशन, हेल्थ केयर, कार्पोरेट कामकाज और गवर्नमेंट जैसे क्षेत्रों में आम लोगों को सेवा देता है। इसके अलावा वह सेना और खुफिया एजेंसियों के कामों में भी मदद करता है। जिसमें एआई आधारित विश्लेषण, सैटलाइट तस्वीरों की प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक्स की योजना बनाना और कमांड-एंड-कंट्रोल में मदद करना शामिल है। अमेरिका खासतौर पर बड़े पैमाने पर क्लाउड सेवाएं देने वाली कंपनियों पर निर्भर है। इनमें अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं। ईरान का मानना है कि इन केंद्रों को निशाना बनाने से जंग की रणनीतियां पूरी तरह बदल जाएंगी और इससे संघर्ष की दिशा पर गहरा असर पड़ सकता है। यूएई इसलिए भी ईरान के निशाने पर है क्योंकि उसका मानना है कि यह अमेरिका, इजरायल के इशारों पर काम करता है और अपनी जमीन का ईरान अमेरिकी हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। शोधकर्ता खालिद वलीद ने लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार 'अल-कुद्स-अल-अरबी' में एक लेख लिखा यह दिखाता है कि अब रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। अब जगहों को नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा है जो निगरानी का काम करती हैं। उन्होंने कहा, इस नजरिए से देखें तो ये कंपनियां अब सिर्फ तकनीकी सेवाएं देने तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सेना के फैसले लेने की प्रक्रिया की चेन का हिस्सा बन गई हैं।

'योगी जी इज ग्रेट': बैडमिंटन कोर्ट पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए सीएम, कर्नाटक से गुजरात तक के जवानों ने की तारीफ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में शनिवार को द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर (बैडमिंटन-टेबल टेनिस) प्रतियोगिता 2025-26 का भव्य शुभारंभ हुआ। गोमतीनगर स्थित बाबू बनारसी दास यूपी बैडमिंटन एकेडमी में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर खिलाड़ियों के साथ हाथ आजमाया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। कर्नाटक पुलिस के काली कृष्णा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अच्छे हैं। यूपी एक अच्छा प्रदेश है।

प्रतियोगिता में 1400 खिलाड़ी लेंगे भाग

दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर (बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस) 2025-26 प्रतियोगिता 9 से 13 मई तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में यूपी पुलिस, गुजरात पुलिस, कर्नाटक पुलिस, उड़ीसा पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस समेत कई राज्यों की टीमें शामिल हुई हैं। आयोजन में करीब 1400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलों की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।

सीएम योगी ने स्मारिका का विमोचन किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगिता की स्मारिका का विमोचन भी किया। वहीं खिलाड़ियों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी कपिल चौधरी ने निभाई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। इसके अलावा 35वीं वाहिनी पीएसी के बैंड द्वारा मधुर स्वर लहरियां प्रस्तुत की गई, जिससे पूरा वातावरण उत्साह और ऊर्जा से भर गया।

खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की

प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। कर्नाटक पुलिस के खिलाड़ी काली कृष्णा ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा प्रदेश है और यहां का माहौल बेहद सकारात्मक है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि वह पहली बार इस

प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं और यहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है।

जबकि उड़ीसा पुलिस के खिलाड़ी देवेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी टीम से नौ खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं।

योगी जी ईज ग्रेट- खिलाड़ी

खिलाड़ी देवेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां क्वालिटी लेवल का अरेंजमेंट किया गया है और सभी खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देवेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी इज ग्रेट। छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाड़ी राजेश मणि सिंह बैडमिंटन के सिंगल, डबल और मिक्स मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में आकर उन्हें हमेशा अच्छा अनुभव मिलता है। उन्होंने बताया कि वे पहले भी प्रतियोगिताओं के लिए उत्तर प्रदेश आ चुके हैं और हर बार यहां बेहतरीन व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं।

गुजरात के 36 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे

राजेश मणि ने कहा कि खिलाड़ियों के रहने, खाने और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति हर खिलाड़ी से व्यक्तिगत रूप से फीडबैक ले रही है, जिससे खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

गुजरात पुलिस के खिलाड़ी रियाज सरवैया टेबल टेनिस मेंस सिंगल और डबल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि गुजरात से 36 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे हैं। रियाज ने कहा कि लखनऊ एक बेहद खूबसूरत और शानदार शहर है। उन्होंने कहा कि यह उनका लखनऊ का पहला दौरा है और यहां का अनुभव काफी यादगार है। रियाज सरवैया ने यूपी पुलिस की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि जिस स्तर का आयोजन यहां किया गया है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में प्रमोशन और डायरेक्ट भर्ती जैसे अवसर देकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो बेहद सराहनीय कदम है।

नवीनीकृत अंधेरी आर एस डाकघर का भविष्य के लिए तैयार सेवा केंद्र के रूप में उद्घाटन

(जीएनएस)।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने 'जन सेवा कनेक्ट' के तहत नवीनीकृत अंधेरी आर एस डाकघर का भविष्य के लिए तैयार सेवा केंद्र के रूप में उद्घाटन किया

अंधेरी आर एस डाकघर को 17 राज्यों के 40 डाकघरों में लागू की जा रही विचार प्रमाण (प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट) पहल के तहत चुना गया है; यह जन सेवा कनेक्ट परियोजना के तहत उद्घाटन किया जाने वाला महाराष्ट्र का पहला और भारत का दूसरा डाकघर बन गया है

प्रविष्टि तिथिः 09 टअ 2026 12:09ढट्ु८ ढक्ह ऊँ

केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने 8 मई 2026 को मुंबई में नवीनीकृत अंधेरी रेलवे स्टेशन (आर एस) डाकघर का उद्घाटन किया। यह डाकघर डाक विभाग की प्रमुख पहल, जन सेवा कनेक्ट के तहत भविष्य के लिए तैयार डाकघर के रूप में स्थापित किया गया है।

(केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में जन सेवा कनेक्ट के तहत पुनर्निर्मित अंधेरी आर एस डाकघर का उद्घाटन करते हुए)

मूल रूप से 1932-33 में स्थापित अंधेरी आर एस डाकघर का जीर्णोद्धार भारतीय डाक विभाग के उन प्रयासों के अंतर्गत किया गया है, जिनका उद्देश्य पारंपरिक डाकघरों को

आधुनिक, ग्राहक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा केंद्रों में परिवर्तित करना है। यह परियोजना नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से शुरू की गई है।

(मुंबई में जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत हाल ही में उद्घाटन किया गया अंधेरी आर एस डाकघर)

जन सेवा कनेक्ट के अंतर्गत 17 राज्यों के 40 डाकघरों में कार्यान्वित की जा रही प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पहल के तहत अंधेरी आर एस डाकघर को चयनित स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है। यह इस पहल के अंतर्गत उद्घाटन किया जाने वाला महाराष्ट्र का पहला और देश का दूसरा डाकघर है।

उन्नत सुविधा में आधुनिक बुनियादी ढांचा और आंतरिक साज-सज्जा, बेहतर ग्राहक सुविधाएं, डिजिटल एकीकरण, कुशल सेवा वितरण प्रणाली और मजबूत ब्रांडिंग और दृश्य पहचान शामिल हैं।

भारतीय डाक विभाग 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क के साथ, देश में वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग ने 2025-26 के दौरान सकल डाक राजस्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो इसकी चल रही परिवर्तनकारी पहलों के प्रभाव को दशार्ती है।

(जन सेवा कनेक्ट के तहत पुनर्निर्मित अंधेरी आर एस डाकघर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर जारी करते हुए गणमान्य व्यक्ति)

जन सेवा कनेक्ट पहल के तहत नवीनीकृत अंधेरी आर एस डाकघर के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र और गोवा सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री अमिताभ सिंह और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने एक विशेष कवर जारी किया।

इस अवसर पर विधायक श्री हारुन खान, श्री रूपेश सावरकर और श्री आचार्य पवन त्रिपाठी भी उपस्थित थे। श्री सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक आधुनिक, भविष्योन्मुखी और नागरिक-केंद्रित डाक अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना को दशार्ती है।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने लोगों को जोड़ने और अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने में भारतीय डाक विभाग की भूमिका पर प्रकाश डाला।

जन सेवा कनेक्ट, भारतीय डाक विभाग की प्रमुख अवसंरचना आधुनिकीकरण पहल है जिसका उद्देश्य डाकघरों को सुलभ, कुशल और डिजिटल रूप से सशक्त सामुदायिक सेवा केंद्रों के रूप में पुनर्परिभाषित करना है। इस पहल के तहत भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र भर में लगभग 2,000 डाकघरों के उन्नयन का प्रस्ताव रखा है।

संजीव गोयनका के भाई ने खोली आईपीएल की पोल, नौटंकी का अड्डा बन चुके टूनामेंट को लेकर बीसीसीआई को चेताया

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 के बीच मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने लीग के भविष्य और इसके गिरते स्तर को लेकर बीसीसीआई को आईना दिखाया है। संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर आईपीएल की गिरती लोकप्रियता पर चिंता जताते हुए कुछ ऐसे आंकड़े और सुझाव साझा किए हैं जो क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गए हैं।

गोयनका के अनुसार आईपीएल की टीवी व्यूअरशिप में लगभग 26 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है और बीसीसीआई को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आईपीएल अब एक क्रिकेट प्रतियोगिता के बजाय केवल बल्लेबाजों की प्रदर्शनी बनकर रह गया है जिससे खेल का रोमांच खत्म हो रहा है।

हर्ष गोयनका ने लीग में सुधार के लिए चार प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है। उनका मानना है कि पिचों को इस तरह संतुलित किया जाना चाहिए जहां गेंदबाजों के लिए भी कुछ मदद मौजूद

हो। गोयनका ने इस बात पर नाराजगी जताई कि हर रात 225 रनों का पीछा करना अब उबाऊ हो चुका है क्योंकि क्रिकेट तभी रोमांचक लगता है जब उसमें अनिश्चितता और संतुलन हो।

इम्पैक्ट प्लेयर ने बिगाड़ा गेम

उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर नियम पर भी दोबारा विचार करने की सलाह दी है जो खेल के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। उनके अनुसार केवल चौके-छक्कों की बरसात ही क्रिकेट नहीं है बल्कि गेंद और बल्ले का संघर्ष ही असली मुकाबला है।

सुविधाओं की खोल दी पोल

मैदान के अंदर के खेल के अलावा गोयनका ने स्टेडियम में फैंस को मिलने वाली सुविधाओं की पोल भी खोल दी। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी को फैंस के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। साथ ही उन्होंने स्टेडियम के खराब अनुभव पर कड़ी आपत्ति जताई और बीसीसीआई से अपील की कि दर्शकों के लिए साफ-सुथरे टॉयलेट्स, बैठने की बेहतर व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण खाना और स्टेडियम तक पहुंचने के आसान रास्तों पर काम किया जाए। गोयनका का मानना है कि जब तक दर्शकों को मैदान पर सम्मान और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक फैंस का मोह भंग होता रहेगा।

गेंदबाजों को बराबरी का मौका देने की सलाह

अंत में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि क्रिकेट तब सबसे अधिक रोमांचक होता है जब मैच में गेंदबाजों की भी उतनी ही भूमिका हो जितनी बल्लेबाजों की। हर मैच में बड़े स्कोर बनना लीग की लोकप्रियता को कम कर रहा है क्योंकि इसमें असली प्रतिस्पर्धा की कमी दिखने लगी है। गोयनका के इन सुझावों के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई आगामी सीजन में खेल के रोमांच को वापस लाने और फैंस की सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाता है।

तीन जन सुरक्षा योजनाएं - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के 11 साल पूरे किए

पीएमजेजेबीवाई के तहत कुल नामांकन 27.43 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और 29.04.2026 तक 21,512.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है

इसी अवधि के दौरान पीएमएसबीवाई के तहत कुल नामांकन 58.09 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और 1,84,662 दावों के लिए 3,667.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है

30.04.2026 तक, 9.04 करोड़ से अधिक लोगों ने एपीवाई योजना में नामांकन किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की गई जनसुरक्षा योजनाएं - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) - समाज के सभी वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इन प्रमुख योजनाओं का लक्ष्य नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं से बचाकर और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देकर बीमा और पेंशन व्यवस्था को व्यापक बनाना है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तीन जन सुरक्षा योजनाओं के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार करते हुए कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कम लागत वाले बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया।'

जन सुरक्षा योजनाओं की 11वीं वर्षगांठ के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत क्रमशः 27 करोड़, 58 करोड़ और 9 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं।

वित्त मंत्री ने पीएमजेजेबीवाई योजना पर कहा कि इस योजना के तहत 10.7 लाख से अधिक परिवारों के 21,500 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटारा किया गया है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पीएमएसबीवाई योजना के तहत 1.84 लाख से अधिक परिवारों के लगभग 3,660 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया गया है।

श्रीमती सीतारमण ने अपने संबोधन के समापन में कहा 'जन सुरक्षा योजनाओं की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर, बैंकों और बीमा कंपनियों के जमीनी स्तर के कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार, जिनके समर्पित प्रयासों से ये योजनाएं इतनी सफल हुई।'

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा, 'इन योजनाओं का उद्देश्य निर्धनतम लोगों को बीमा कवरेज और पेंशन सहायता प्रदान करना है। योजनाओं में नामांकन और दावों की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और सरल करने पर ध्यान दिया गया है। ऑनलाइन जन सुरक्षा पोर्टल के शुरू होने से नागरिकों के लिए बैंक शाखाओं या डाकघरों में जाए बिना आसानी से नामांकन करना संभव हुआ है। दावा प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से त्वरित निपटान सुनिश्चित हुआ है, जिससे शोक संतप्त परिवारों को सबसे अधिक आवश्यकता के समय सहायता मिल सकी है।'

जन सुरक्षा की तीन योजनाओं - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की 11वीं वर्षगांठ मनाते हुए, आइए हम याद करें कि कैसे इन योजनाओं ने लोगों को किफायती बीमा और सुरक्षा (जन सुरक्षा) प्रदान की है, इनकी उपलब्धियां और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए प्रतिदिन 2 रुपये से कम के प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

योजना की मुख्य विशेषताः पीएमजेजेबीवाई एक वर्षीय बीमा योजना है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। यह योजना एलआईसी और अन्य जीवन बीमा कंपनियों जो आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और बैंकों/डाकघरों के साथ साझेदारी करने के बाद समान शर्तों पर यह उत्पाद प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं, द्वारा संचालित की जाती है। सहभागी बैंक/डाकघर अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने हेतु किसी भी जीवन बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पात्रता शर्तेः योजना में भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत खाताधारक, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/चालू करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। यदि किसी व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघरों में एक से अधिक खाते हैं, तो वह केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही योजना में शामिल होने के पात्र है।

नामांकन अवधिः यह कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर निर्धारित व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल होने/भुगतान करने का विकल्प आवश्यक होगा।

प्रीमियमः 436/- रुपये प्रति वर्ष प्रति सदस्य। योजना में नामांकन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार, प्रीमियम खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से एक ही किश्त में काट लिया जाएगा। भावी कवरेज के लिए विलंबित नामांकन नीचे लिखे अनुसार आनुपातिक प्रीमियम के भुगतान के साथ संभव है;

क) जून, जुलाई और अगस्त में नामांकन के लिए झ 436/- रुपये का पूरा वार्षिक प्रीमियम देय है।

ख) सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नामांकन के लिए आनुपातिक प्रीमियम के रूप में 342/- रुपये देय है।

ग) दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नामांकन के लिए आनुपातिक प्रीमियम 228/- रुपये देय है।

घ) मार्च, अप्रैल और मई में नामांकन के लिए आनुपातिक प्रीमियम 114/- रुपये देय है।

लाभः ग्राहक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। नामांकन की तिथि से 30 दिनों की ग्रहणाधिकार अवधि लागू होगी।

उपलब्धियांः 29.04.2026 तक, पीएमजेजेबीवाई के तहत कुल नामांकन 27.43 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और 10,75,625 दावों के लिए 21,512.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

29.04.2026 तक, इस योजना में 12.72 करोड़ महिलाओं ने नामांकन करवाया है और पीएमजेडीवाई खाताधारकों में से 8.09 करोड़ लोगों ने नामांकन करवाया है।

स्रोतः कुल नामांकन के लिए बैंक और बीमा कंपनियां, महिला लाभार्थियों के लिए बैंक और पीएमजेडीवाई खाताधारक

स्रोतः बीमा कंपनियाँ

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 2 लाख रुपये तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसका न्यूनतम प्रीमियम 2 रुपये प्रति माह से कम है।

योजना की मुख्य विशेषताः पीएमएसबीवाई एक साल का कवर है, जिसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि महाराणा प्रताप वीरता और शौर्य के अमर प्रतीक हैं। इस महान योद्धा ने मातृभूमि के सम्मान, गौरव और गरिमा की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और अटूट आत्मसम्मान की गाथा आने वाली पीढ़ियों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती रहेगी।

श्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया;

'वीरता और पराक्रम के अमर प्रतीक, देश के महान योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने मातृभूमि की आन-बान और शान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके अदम्य साहस और अटूट स्वाभिमान की गाथाएं युगों-युगों तक देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति का दीप प्रज्वलित करती रहेंगी।'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पोचीशे बोइशाख के अवसर पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पोचीशे बोइशाख के विशेष अवसर पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के लेखक, विचारक और कवि थे, जिन्होंने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की एक शाश्वत आवाज के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने मानवता की गहरी भावनाओं और भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च आदर्शों को अभिव्यक्ति दी। गुरुदेव ने समाज को नए विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से समृद्ध किया।

श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र गुरुदेव टैगोर को गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि गुरुदेव के विचार लोगों के मन को प्रकाशित करते रहेंगे और उनके प्रयासों में उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा;

आज, पोचीशे बोइशाख के विशेष अवसर पर, हम गुरुदेव टैगोर को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उन्होंने एक विशिष्ट दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मानवता की गहरी भावनाओं और हमारी संस्कृति के उच्च आदर्शों को अभिव्यक्ति दी। उन्होंने नए विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से हमारे समाज को समृद्ध किया।

हम उन्हें गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। उनकी विचारधाराएं हमारे मन को प्रकाशित करती रहें और हमारे प्रयासों में मार्गदर्शन करती रहें।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सीएम योगी समेत कई मंत्री आज लोकभवन में देखेंगे 'कृष्णावतारम', राज्यपाल की नतिनी ने फिल्म में निभाया है अहम किरदार

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लोकभवन ऑडिटोरियम में 'कृष्णावतारम' फिल्म देखेंगे।

(जीएनएस)।

लखनऊ। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री रविवार को लोकभवन ऑडिटोरियम में फिल्म 'कृष्णावतारम' (लार्ड कृष्णा) देखेंगे।

फिल्म का प्रसारण शाम चार बजे से किया जाएगा। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित इस फिल्म में

राज्यपाल की नतिनी संस्कृति जयना सत्यभामा का रोल किया है।

पिछले महीने इस फिल्म के निर्देशक हार्दिक गज्जर व कलाकारों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि भारतीय संस्कृति और विरासत पर आधारित ऐसी फिल्मे बननी चाहिए।

सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण, सुष्मिता भट्ट ने राधा, निवाशिनी कृष्णन ने रुक्मिणी और संस्कृति जयना ने सत्यभामा की भूमिका निभाई हैं। यह फिल्म सात मई को ही रिलीज हुई है।

फिल्म भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा की कहानी पर आधारित है। सत्यभामा की भूमिका निभाने वाली संस्कृति जयना की यह पहली फिल्म है। फिल्म में भगवान श्रीकृष्ण की द्वारका से कुरुक्षेत्र तक की यात्रा का वृतांत है।

पंजाब में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हिंसक प्रदर्शन, बठिंडा में पत्रकारों पर दबाव के खिलाफ प्रदर्शन

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा)

सूरत। आज देशभर में पत्रकारों को सच लिखने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, और इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं जहां सच का साथ देने वाले पत्रकारों को मौत तक की सजा भुगतनी पड़ी है। मंगलवार को पंजाब के बठिंडा शहर में बड़ी संख्या में पत्रकार, किसान प्रतिनिधि और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के कार्यालय के बाहर जमा हुए और उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। "प्रेस दी आजादी बहाल करो संघर्ष समिति" द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य में प्रेस की आजादी पर हो रहे हमलों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि स्वतंत्र पत्रकारिता को अधिकारियों द्वारा सुनियोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इस विवाद के केंद्र में पत्रकार मनिंदरजीत सिंह सिद्धू के सोशल मीडिया पेज को बंद करने की घटना है। आरोप है कि सिद्धू द्वारा बठिंडा के जियोंद गांव में विवादास्पद मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। अंत में, सभा ने चेतावनी दी कि पत्रकारों को डराना और उनके काम में दखल देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

समिति ने स्पष्ट धमकी दी है कि यदि अवरुद्ध पृष्ठों को बहाल नहीं किया गया और पत्रकारों के खिलाफ "झूठे मामले" वापस नहीं लिए गए, तो आने वाले दिनों में राज्य भर में आंदोलन तेज किया जाएगा।

वडोदरा में गणेश प्रतिमा विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, उच्च न्यायालय ने आरोपियों के जुलूस पर सख्त रुख अपनाया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा)

सूरत। पुलिस ने 2025 में वडोदरा में गणेश उत्सव के अवसर पर श्री गणेशजी की प्रतिमा पर अंडे फेंककर शांति भंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। यह भी पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाबालिग था।

पुलिस ने आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस निकालकर जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी भी मांगी। पिछले साल अगस्त में पानीगेट के पास श्रीजी की प्रतिमा पर अंडे फेंकने की घटना को लेकर वडोदरा में विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में पुलिस पर अदालत की अवमानना का आरोप भी लगा है। क्राइम ब्रांच और सिटी पीआई समेत छह अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

हाई कोर्ट ने पांच आरोपियों की याचिका स्वीकार कर ली है। हाई कोर्ट ने कहा है कि पुनर्निर्माण के नाम पर जुलूस नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के निदेशों का उल्लंघन करते हुए आरोपियों का जुलूस निकालने के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। यह घटना पिछले साल अगस्त में पानीगेट के पास हुई थी। जिसके कारण तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शहर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है।

लखनऊ में अपना दल कमेरावादी पार्टी का यूजीसी के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन, रेलवे इंजन पर चढ़ीं विधायक डॉ पल्लवी

कमेरावादी पार्टी के साथ लखनऊ में विभिन्न सामाजिक और छात्र युवा संगठनों ने विशाल मार्च निकाला।

(जीएनएस)।

लखनऊ। अपना दल कमेरावादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने शनिवार को लखनऊ में हजारों समर्थकों के साथ यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कौशांबी के सिराथू विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर हजारों समर्थकों के साथ चक्का जाम किया।

अपना दल कमेरावादी पार्टी के साथ लखनऊ में विभिन्न सामाजिक और छात्र युवा संगठनों ने विशाल मार्च निकाला। इस दौरान विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने कहा कि हम यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू कराने के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। चारबाग रेलवे स्टेशन से निकले जुलूस को आरक्षण केंद्र पर बैरिकेडिंग लगाकर रोके जाने से आक्रोशित डॉ पल्लवी पटेल ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रेलवे ट्रैक पर उतरकर चक्का जाम कर दिया।

जिससे दिल्ली से अयोध्या जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को आउटर पर रोक दिया गया, जो लगभग एक घंटे लेट हो गई और स्टेशन पर आवागमन प्रभावित हो गया। पुलिस कर्मियों और कार्यकताओं में नोक-झोक भी हुई। पुलिस और रेल के अधिकारियों ने मशक्कत के बाद ट्रेन के इंजन पर चढ़ीं विधायक डॉ पल्लवी पटेल को उतारा। इसके बाद विधायक समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकताओं को हिरासत में ले लिया गया।

प्रदर्शनकारियों ने "यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू करो", "हम सबका है ऐलान, सबको शिक्षा सबको मान", "शिक्षण संस्थानों में वंचितों का उत्पीड़न बंद करो" आदि नारे लगाते हुए हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता व सिराथू विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने कहा कि जाति, लिंग धर्म या अक्षमता के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव एवं उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निदेशों के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 लाया गया। जिसे तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझने की बजाय कुतर्कों के आधार प्रायोजित विरोध की आड़ में न्यायिक प्रक्रिया में ले जाकर फंसा दिया गया, एक अस्थाई स्थगन के आधार पर विश्वविद्यालयों में समता स्थापित करने वाले विनिमय 2026 को न्यायालय में लंबित कर दिया गया।

विधायक ने कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने वाली भाजपा सरकार की नियत कभी भी इस देश के वंचित एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के प्रति ठीक नहीं रही है। अगड़ा और पिछड़ा के बीच में खाई को और चौड़ा करने तथा जनता की बुनियादी कमाई दवाई एवं पढ़ाई जैसे सवालों पर सरकारों की विफलता से ध्यान हटाने के दोहरी लाभ की साजिशों के तहत यह सब किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तडवी, अनिल कुमार जैसे ज्ञात और अनगिनत अज्ञात पीड़ितों साथ हुई घटनाओं के पुनरावृति को रोकने के लिए तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के अवसरों में समानता के लिए बनाए जा रहे प्रावधानों को भ्रामक बहसों एवं अफवाहों में फंसा कर पीड़ितों के साथ न्याय के लिए बनाए गए यूजीसी विनिमय 2026 को अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई का हथियार बना दिया गया। जबकि यह विनियम किसी भी तरीके से किसी खास सामाजिक समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि हर तरह के शोषक के खिलाफ तथा शोषण परंपराओं पर रोक के लिए है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, बड़े सुनियोजित साजिश के तहत यूजीसी रेगुलेशन 2026 को न्यायिक प्रक्रिया में फंसा कर इससे होने वाले वोट के लाभ हानि के जोड़ घटाना में लग गई है। वंचित समुदाय का दमन बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि ऐसी दमनकारी व्यवस्था और घोर अन्याय के खिलाफ अब सड़क पर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, सामाजिक न्याय के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लागू करने के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे।

विधायक पल्लवी पटेल पर एफआईआरः लखनऊ में ट्रेन पर चढ़कर नारेबाजी करना पड़ा भारी, 350 समर्थकों पर भी मुकदमा

लखनऊ चारबाग स्टेशन पर प्रदर्शन को लेकर विधायक पल्लवी पटेल पर फ्छत्र ने त्रक्षफ्र दर्ज की है. यूजीसी रेगुलेशन की मांग को लेकर ट्रेन के इंजन पर चढ़ने और रेलवे एक्ट के उल्लंघन का आरोप..

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के सिराथू से अपना दल (कामेरावादी) की विधायक डॉ. पल्लवी पटेल के खिलाफ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने और प्रदर्शन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. आरपीएफ ने विधायक और उनके करीब 350 अज्ञात समर्थकों पर रेलवे एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है.

दरअसल, शुक्रवार को डॉ. पल्लवी पटेल के नेतृत्व में अपना दल (कमेरावादी) के कार्यकर्ता 'यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026' को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन के सरकुलेटिंग एरिया में प्रदर्शन कर रहे थे. दोपहर करीब 1:16 बजे प्रदर्शनकारियों का जत्था अचानक दौड़ते हुए एस्केलेटर के पास वाले गेट से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अनाधिकृत रूप से दाखिल हो गया.

रेलवे ट्रैक और इंजन पर प्रदर्शन

विधायक पल्लवी पटेल अपने कार्यकताओं के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच खड़ी निरीक्षण यान (परख डीपीसी) पर चढ़ गईं और नारेबाजी करने लगीं. इस दौरान स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

भारी सुरक्षा बल ने हटाया

स्टेशन पर तैनात आरपीएफ निरीक्षक भूपेंद्र सिंह, जीआरपी और सिविल पुलिस बल ने विधायक और उनके समर्थकों को काफी मशक्कत के बाद दोपहर करीब 1:25 बजे स्टेशन परिसर से बाहर किया. पुलिस के अनुसार, उस समय कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर गिरफ्तारी करना संभव नहीं था, लेकिन सबूतों के आधार पर अब कानूनी शिकंजा कसा गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

आरपीएफ ने विधायक पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों के कृत्य को 'असंवैधानिक' करार देते हुए रेलवे एक्ट की धाराओं 147 (रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश), धारा 145 (सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव) और धारा 156 (ट्रेन की छत, इंजन या पायदान पर चढ़कर यात्रा या प्रदर्शन करना) के तहत केस दर्ज किया है.

राजनीतिक गलियारों में हलचल

पल्लवी पटेल का यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ एक बड़े विरोध के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थल पर इस तरह के प्रदर्शन ने सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लखनऊ के अंसल प्रॉपर्टी ठगी मामले की अब ईओडब्लू करेगी जांच, 30 से ज्यादा आरोपी रडार पर

लखनऊ में फ्लैट और प्लॉट ठगी से जुड़े चर्चित अंसल प्रकरण की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा करेगी। क्राइम ब्रांच ने 30 से अधिक आरोपियों की पहचान की है।

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी में फ्लैट और प्लाट के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित ठगी से जुड़े चर्चित अंसल प्रकरण की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) करेगी। क्राइम ब्रांच द्वारा अंसल से जुड़े मामलों की जांच स्थानांतरित करने की तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

क्राइम ब्रांच ने इस बारे में प्रस्ताव भी भेजा था जिसे कुछ आपत्तियां लगाकर वापस कर दिया गया था। क्राइम ब्रांच अब उन आपत्तियों को दूर कर फिर से जांच के लिए पत्र भेज रही है। क्राइम ब्रांच की जांच में अब तक 30 से अधिक आरोपितों को चिन्हित किया है जिसमें अंसल के मालिक, प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग एजेंट और अन्य सहयोगी शामिल हैं।

अंसल प्रापर्टी घोटाले में राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी और गोमतीनगर थाने में 328 मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि कंपनी ने लोगों से प्लाट और फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपये वसूले, लेकिन तय

समय पर कब्जा नहीं दिया।

कई मामलों में एक ही संपत्ति को अलग-अलग लोगों को बेचने और वादे के अनुरूप विकास कार्य न कराने की शिकायतें भी सामने आईं। पीड़ितों में लखनऊ के अलावा नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी समेत कई जिलों के खरीदार शामिल हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने सभी मुकदमों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी। पिछले कई महीनों से क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमें दस्तावेजों की पड़ताल कर रही थीं। जांच के दौरान बड़ी संख्या में पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगभग सभी मामलों में ठगी का तरीका एक जैसा मिला, जिससे मुकदमों में लगाए गए आरोप प्राथमिक जांच में सही पाए गए। सूत्रों के अनुसार 328 मुकदमों को कई पुलिसकर्मियों के बीच बांटकर जांच कराई गई थी।

सभी टीमों ने अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप दी है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर 50 से अधिक संदिग्ध लोगों की सूची तैयार की गई, जिनमें से 30 से अधिक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही थी। इसके लिए सवालों की सूची तैयार कर नोटिस भेजे गए थे।

हालांकि क्राइम ब्रांच का मानना है कि मामला बड़े आर्थिक अपराध और व्यापक वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराना अधिक प्रभावी होगा। इसी कारण केस ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज की गई थी।

पुलिस अधिकारियों के तरफ से जैसे-जैसे जांच को ईओडब्ल्यू भेजी गई थी, लेकिन कुछ आपत्तियां लगाकर वापस कर दी गई थी। ऐसे में उन आपत्तियों को दूर करने के लिए अपराध शाखा उन साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है। इसके बाद फिर से जांच को ईओडब्ल्यू भेजी जाएगी ताकि जल्द से जल्द आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

कानपुर-लखनऊ रेल यात्रियों के लिए खुशखबरीः गंगा ब्रिज पर 42 दिन का ब्लॉक खत्म, अब 14 मई से 75 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

गंगा रेलवे ब्रिज पर 42 दिन का ब्लॉक 13 मई को समाप्त हो रहा है, जिससे 14 मई से कानपुर-लखनऊ ट्रैक पर ट्रेनें 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। ..

(जीएनएस)।

कानपुर। गंगा रेलवे ब्रिज पर 42 दिन का ब्लाक 13 मई को खत्म हो जाएगा। 14 मई की सुबह से लखनऊ-कानपुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। ट्रैक पर अब नए स्टील स्लीपर डालने का काम अंतिम चरण में है। इसी क्रम में शुक्लागंज में गंगा

रेलवे क्रासिंग से गंगा घाट (कानपुर पुल बायां किनारा) स्टेशन यार्ड में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो गया है।

गंगा रेलवे ब्रिज पर मौजूद इंजीनियरों ने बताया कि पिछले साल भी एक ट्रैक पर स्लीपर बदले गए थे। इस बार डाउन में भी ट्रैक पर स्लीपर बदल गए हैं। अब अगले 30-40 साल के लिए ट्रैक बहुत मजबूत हो गया है। इस ब्रिज पर पुराने ट्रैक पर 15-30-20 किमी प्रति घंटा की गति से ट्रेनें निकल पा रही थीं, लेकिन ट्रैक पर स्लीपर बदल जाने से ट्रेनें 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में भी गंगा ब्रिज को आसानी से पार कर सकेंगी।

शनिवार दोपहर तक ब्रिज पर स्लीपर डालने का काम शुक्लागंज रेल क्रासिंग से करीब 30-40 मीटर शेष बचा था। यहां 20-25 श्रमिक स्लीपर डालने और ट्रैक से पुरानी पटरियां और लोहे की चादरों को उखाड़कर नई डालने में जुटे थे। पुरानी पटिया की लंबाई अधिक होने से गैस बिल्डिंग राड से उसे काटा जा रहा था। वहीं, माल वाहक ट्रेलर ट्रेन से नए स्पीलर भी लाकर उतारे जा रहे थे। गंगा ब्रिज के डाउन ट्रैक पर 1,710 स्टील स्लीपर पड़ने हैं। इसमें शुक्रवार तक 1,535 स्लीपर पड़ चुके थे। शेष 175 स्लीपरों को मजदूर ट्रैक पर डालने में व्यस्त थे।

इन ट्रेनों का भी शुरू हो जाएगा संचालन

गंगा रेल ब्रिज (डाउन लाइन) की मरम्मत के लिए दो अप्रैल से 13 मई तक सुबह 09:30 से शाम 05:30 बजे तक के मेगा ब्लाक की वजह से कानपुर-लखनऊ मेमू समेत डाउन की 70-80 ट्रेनों का परिचालन बंद है। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, अयोध्या वंदेभारत सहित 29 से अधिक के बदले मार्ग या बीच के स्टेशनों पर टर्मिनेट होकर वापस भेजी गई हैं। इनमें से कानपुर से होकर जाने वाली तीन ट्रेनें एक अप्रैल से ही निरस्त हैं।

आईसीजीएस अचल भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ

(जीएनएस)।

भारतीय तटरक्षक बल ने 9 मई, 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक पोत (आईसीजीएस) अचल को सेवा में शामिल कर अपनी परिचालन क्षमता को और मजबूत किया है। यह नई पीढ़ी की अदम्य-श्रेणी में तीव्र गति के जहाजों की श्रृंखला का नवीनतम पोत है। इस जहाज के अचल नाम होने का अर्थ 'अडिग' है, जो भारतीय तटरक्षक बल की राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा, समुद्र में जीवन बचाने और भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ता है। यह अत्याधुनिक पोत समुद्री अभियानों की व्यापक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है, जिनमें तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज एवं बचाव (एसएआर), तस्करी-रोधी अभियान तथा समुद्री प्रदूषण से निपटने जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

इस जहाज को रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव एवं महानिदेशक (अधिग्रहण) ए. अंबरासु ने औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक

बल में शामिल किया। इस अवसर पर तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर-पश्चिम) के कमांडर इंस्पेक्टर जनरल टेकुर शशि कुमार, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यह समारोह अत्यंत गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ।

मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित यह पोत भारत की पोत निर्माण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। 50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटकों से सुसज्जित यह जहाज रक्षा निर्माण क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दशार्ता है। साथ ही, यह भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' गतिविधियों के अनुरूप स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है।

आईसीजीएस अचल का सेवा में शामिल होना भारतीय तटरक्षक बल के मौजूदा बेड़ा विस्तार कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अत्याधुनिक पोत के शामिल होने से तटीय सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी, साथ ही समुद्री निगरानी एवं परिचालन तत्परता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा।

लखनऊ में भाजपा नेता पर हमला, बदमाशों ने गोलियों से भूना, अस्पताल में भर्ती

लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता चेतन पर जानलेवा हमला हुआ है. थाना बाजार खाला क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी कमर में दो गोलियां लगी हैं.

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज मामला आया है, जहां थाना बाजार खाला क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक बीजेपी (इखढ) नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस जानलेवा हमले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता को दो गोलियां लगी हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

सूत्रों से मिली शुरूआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता चेतन को निशाना बनाते हुए फायरिंग की. इस हमले में चेतन की कमर पर दो गोलियां लगी हैं और

वे बुरी तरह लहूलुहान होकर गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने में जुटी हुई है. उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

ट्रामा सेंटर के बाहर भारी भीड़,

पुलिस अलर्ट

सत्तारूढ़ पार्टी के युवा नेता पर सरेआम हुए इस जानलेवा हमले की खबर मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. घटना की जानकारी पाते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा (इख ट) और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में ट्रामा सेंटर पहुंच गए हैं. अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा है और हालात को देखते हुए पुलिस फोर्स भी अलर्ट मोड पर है.

आपसी रंजिश का शक

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. सूत्रों की मानें तो इस जानलेवा हमले के पीछे पुरानी 'आपसी रंजिश' बताई जा रही है. हालांकि, हमलावर कौन थे और किस वजह से गोली मारी गई, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है.

योगी मंत्रिमंडल का विस्तार दोपहर 3:30 बजे, लोकभवन से नेताओं को गया फोन; सीएम ने की राज्यपाल से मुलाकात

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को होने जा रहा है। टीम योगी में छह नए चेहरे शामिल होंगे। योगी कैबिनेट के 2022 में गठन के बाद दूसरा विस्तार होने जा रहा है। यूपी चुनाव 2027 से पहले इस विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3.30 बजे से जनभवन में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले शनिवार शाम राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने इस मुलाकात के दौरान एक किताब भेंट की थी। साथ ही, मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वाले नामों की सूची भी सौंपी गई। शपथ लेने वालों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय, पूजा पाल, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान और हंसराज विश्वकर्मा के नाम शामिल हैं।

जनभवन से भेजी गई सूचना

जनभवन से देर रात तक शपथ लेने वाले नए चेहरों को सूचना भेजी गई। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण 25 मार्च 2022 को हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दो उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक समेत 52 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें 18 कैबिनेट, 14 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्यमंत्री शामिल थे। योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले 5 मार्च 2024 को हुआ था।

योगी कैबिनेट के पहले विस्तार में चार कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के अनिल

कुमार और भाजपा के सुनील कुमार शर्मा एवं दारा सिंह चौहान शामिल थे। इस तरह मंत्रियों की संख्या बढ़कर 56 हो गई थी। जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद चुने जाने के बाद टीम योगी के सदस्यों की संख्या घटकर 54 रह गई थी।

सीएम ने की थी राज्यपाल से मुलाकात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम लखनऊ में जनभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि रविवार या सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में छह नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की चर्चा है। हालांकि, अभी तक इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। सीएम योगी पिछले समय में उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद इस मुलाकात के बाद चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है।

राज्यपाल को भेंट की पुस्तक

सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के दौरान उन्हें लालचंद राम की लिखित पुस्तक 'भारतीय ज्ञान परंपरा अवधारणा' भेंट की। सीएम ऑफिस की ओर से राज्यपाल से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। दूसरी तरफ, लखनऊ के सियासी महकमे में कैबिनेट विस्तार की चर्चा शनिवार दोपहर बाद से ही गरमाई हुई है। योगी सरकार में शामिल होने वाले छह नाम भी सामने आए।

मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच चर्चा में आए नामों को रविवार को राजधानी लखनऊ में ही रहने को कहा गया है। मंत्रिमंडल में छह नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही थी।

फेरबदल की उम्मीद नहीं

योगी मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों के काम को लेकर पिछले दिनों सवाल उठे थे। सीनियर नेतृत्व इससे खुश नहीं था। हालांकि, चुनाव नजदीक आने के कारण दावा किया जा रहा है कि अब कैबिनेट का विस्तार तो होगा, लेकिन न तो कोई मंत्री हटाया जाएगा और न ही किसी का विभाग बदला जाएगा। इससे मंत्रिमंडल से नाम कटने से आशंका से परेशान नेताओं को कुछ हद तक राहत मिलती दिख रही है।

लखनऊ की जल सुरक्षा होगी और मजबूत, गोमती बैराज के बदल रहे हैं गेट; योगी सरकार का आधुनिकीकरण पर जोर

(जीएनएस)।

लखनऊ। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत राजधानी स्थित गोमती बैराज को आधुनिक और आदर्श बैराज सिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने बैराज के पुराने और क्षतिग्रस्त वर्टिकल गेटों को बदलने का कार्य शुरू कर दिया है। इससे राजधानी लखनऊ की पेयजल आपूर्ति और अधिक मजबूत होगी। इसके अलावा जल सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरणीय संतुलन को नई तकनीक के माध्यम से और मजबूती मिलेगी।

बैराज के गेटों में जैविक एवं रासायनिक क्षरण बढ़ने से कार्यक्षमता होने लगी थी प्रभावित

प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग ने बताया कि वर्ष 1980 से 1983 के बीच निर्मित गोमती बैराज लंबे समय से राजधानी की जल आपूर्ति व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। यह बैराज कुड़िया घाट पंपिंग स्टेशन पर 105.6 मीटर का निर्धारित जल स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लाखों लोगों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध हो पाता है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में गोमती नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित कर शहर को बाढ़ जैसी स्थितियों से बचाने में भी यह अहम योगदान देता है। उन्होंने बताया कि समय के साथ नदी के पानी की गुणवत्ता और

लगातार उपयोग के कारण बैराज के गेटों में जैविक एवं रासायनिक क्षरण बढ़ गया था। इससे गेटों की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगी थी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चरणबद्ध तरीके से गेट बदलने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में वर्ष 2024 में दो गेट बदले गए थे, जबकि 2025 में चार अन्य गेटों को प्रतिस्थापित किया गया। अब अंतिम चरण में शेष चार गेटों के निर्माण और स्थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

मुख्य अभियंता यांत्रिक उपेंद्र सिंह ने बताया कि इन गेटों का निर्माण बरेली स्थित आईएसओ प्रमाणित सिंचाई कार्यशाला में किया गया है। प्रत्येक गेट दो स्तरों में तैयार किया गया है, जिसमें ऊपरी हिस्से का वजन लगभग 16 टन और निचले हिस्से का वजन करीब 18 टन है। सभी दस गेटों की चौड़ाई 18 मीटर तथा ऊंचाई 4.95 मीटर निर्धारित की गई है। अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत संरचना वाले ये नए गेट लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। उन्होंने बताया कि विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती गेट बदलने के दौरान राजधानी की पेयजल आपूर्ति को प्रभावित न होने देना था। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने बैराज के ऊपरी हिस्से में कॉफरडैम का निर्माण कराया है, ताकि मरम्मत और प्रतिस्थापन कार्य के दौरान जल स्तर को नियंत्रित रखा जा सके। इस व्यवस्था से कुड़िया घाट पंपिंग स्टेशन तक पर्याप्त पानी पहुंचता रहेगा और शहरवासियों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बैराज को स्काडा तकनीक से स्वचालित रूप में संचालित करने की हो रही तैयारी

मुख्य अभियंता ने बताया कि मरम्मत और गेट प्रतिस्थापन कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए 8 मई से 15 जून तक कुल 45 दिनों की बंदी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने के कारण जल स्तर में गिरावट की संभावना को देखते हुए विभाग चौबीसों घंटे काम कर रहा है ताकि कार्य समय से पहले पूरा किया जा सके। इसके लिए इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों की विशेष टीम लगातार निगरानी कर रही है। बैराज को स्काडा तकनीक से स्वचालित रूप में संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इससे बैराज के गेटों का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। जल स्तर की निगरानी, गेटों का नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया जैसी व्यवस्थाएं अधिक प्रभावी बनेंगी। इससे मानवीय त्रुटियों में कमी आएगी और पूरी प्रणाली अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी होगी।

यूपी की राजनीति में होगा बड़ा फेरबदल, योगी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं 10 नए नेता

(जीएनएस)।

योगी सरकार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है. जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कल शाम कैबिनेट का विस्तार हो सकता है. इसे लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं. माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद नए मंत्रियों के नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

9 से 10 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ

जानकारी के मुताबिक इस बार योगी कैबिनेट में 9 से 10 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं. इसके साथ ही कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव होने की संभावना है. सरकार जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में जुटी है.

इन नेताओं के नाम चर्चा में

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं. इनमें भूपेंद्र चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है. वह जाट (ओबीसी) समाज से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी हैं तथा मुरादाबाद के रहने वाले हैं. वहीं मनोज पांडेय ब्राह्मण समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी के बागी नेता माने जाते हैं और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं. साथ ही पूजा पाल को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है. वह पाल (ओबीसी) समाज से आती हैं, सपा की बागी नेता हैं और कौशांबी के चायल से विधायक हैं. इसके अलावा अशोक कटारिया का नाम भी चर्चा में है, जो गुर्जर (ओबीसी) समाज से आते हैं, एमएलसी हैं और बिजनौर के रहने वाले हैं. कृष्णा पासवान, जो पासी (एससी) समाज से आती हैं और फतेहपुर की खागा सीट से विधायक हैं, उनका नाम भी संभावित सूची में शामिल बताया जा रहा है. वहीं सुरेश पासी, जो अमेठी के जगदीशपुर से विधायक हैं और पासी (एससी) समाज से आते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है.

कई मंत्रियों के विभाग बदलने की भी चर्चा

सूत्रों का कहना है कि इस विस्तार में सिर्फ नए मंत्री ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि कई मौजूदा मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल सभी की नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन में होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं.

लेडीबर्ड बीटल से कीटों पर लगेगी लगाम, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ करेगा शोध, चार लाख का बजट स्वीकृत

(जीएनएस)।

लखनऊ। लेडीबर्ड बीटल सामान्यतः माहू या लाही जैसे कीटों का शिकार करती है। वैज्ञानिक अब यह समझने का प्रयास करेंगे कि लेडीबर्ड के रासायनिक अवशेष और गंध एफिड्स के व्यवहार, भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, विकास और प्रजनन दर को किस तरह प्रभावित करते हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में अब कृषि में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प पर शोध किया जाएगा। प्रदेश सरकार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत इस परियोजना के लिए चार लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। शोध में लेडीबर्ड बीटल के प्राकृतिक रासायनिक संकेतों का उपयोग कर हानिकारक कीटों के नियंत्रण की संभावनाओं का अध्ययन होगा।

शोध का मुख्य फोकस लेडीबर्ड बीटल के 'नॉन-कंजम्पटिव प्रभावों' पर रहेगा। लेडीबर्ड बीटल सामान्यतः माहू या लाही जैसे कीटों का शिकार करती है। वैज्ञानिक अब यह समझने का प्रयास करेंगे कि लेडीबर्ड के रासायनिक अवशेष और गंध एफिड्स के व्यवहार, भोजन ग्रहण करने की

प्रवृत्ति, विकास और प्रजनन दर को किस तरह प्रभावित करते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, लेडीबर्ड की उपस्थिति से पैदा होने वाला 'भय का मनोविज्ञान' हानिकारक कीटों को फसलों से दूर रखने और उनकी आबादी सीमित करने में प्रभावी हो सकता है। शुरूआती प्रयोगशाला अध्ययनों में लेडीबर्ड बीटल के अर्क के प्रभाव से एफिड्स की जीवित रहने की क्षमता में कमी और उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिला है।

वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कीट नियंत्रण के लिए सिंथेटिक कीटनाशकों का व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो जाती है। विश्वविद्यालय की सहायक आचार्या तृप्ति यादव के नेतृत्व में होने वाला यह शोध समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) के सिद्धांतों के अनुरूप स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प विकसित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परियोजना भविष्य में बायो-पेस्टिसाइड के विकास के नए रास्ते खोलेगी, जिससे किसानों को कम लागत और सुरक्षित कीट नियंत्रण तकनीक मिल सकेगी। इससे फसलों की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

सहायक आचार्या एवं शोध सहायक, जंतु विज्ञान विभाग, तृप्ति यादव के अनुसार इस शोध का उद्देश्य लेडीबर्ड के रासायनिक अवशेषों और गंध के प्रभावों को समझना है। ये अवशेष एफिड्स के व्यवहार, भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, विकास और प्रजनन दर को प्रभावित करते हैं। लेडीबर्ड की उपस्थिति से उत्पन्न 'भय का मनोविज्ञान' कीटों की आबादी सीमित करने में प्रभावी हो सकता है।

महंगे सिलिंडर और बुकिंग की झंझट से कब मिलेगी मुक्ति? लखनऊ की इन बड़ी कॉलोनियों में अब तक नहीं पहुंची पीएनजी लाइन

(जीएनएस)।

लखनऊ। सरकार एक तरफ पीएनजी कनेक्श बढाने पर जोर दे रही है वहीं दूसरी तरफ शहर में कई ऐसी सड़कें और मुहल्ले हैं जहां पाप लाइन डालने में ही लापरवाही बरती गई है। एकता नगर, पाठकपुरम , कृष्ण विहार और उतरेटिया सहित क्षेत्र की घनी आबादी वाली कालोनियां आज भी पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी लाइन की सुविधा से वंचित हैं।

स्थानीय निवासियों ने विभाग की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में सैकड़ों मकान होने के बावजूद अब तक पीएनजी लाइन नहीं डाली गई, जबकि आसपास की छोटी-छोटी नई कालोनियों तक यह सुविधा पहुंच चुकी है।

उतरेटिया निवासी अमर सिंह ने बताया कि उनका इलाका काफी पुराना है और यहां लंबे समय से बड़ी आबादी निवास कर रही है, लेकिन आज तक पीएनजी लाइन नहीं बिछाई गई।

उन्होंने कहा कि कई नई और छोटी कॉलोनियों में गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है, जबकि पुराने मोहल्लों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा, हम लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। हर घर में गैस सिलेंडर की समस्या बनी रहती है। अगर पीएनजी लाइन आ जाए तो लोगों को काफी राहत मिलेगी।

पाठक पुरम ज्ञानती यादव ने बताया कि उनकी पाठक पुरम कालोनी रायबरेली रोड से जुड़ी हुई है और मुख्य मार्ग के बेहद करीब होने के बावजूद विभाग ने यहां अब तक कोई काम शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा, जब मुख्य सड़क के आसपास की कालोनियों में सुविधा पहुंच सकती है तो हमारे इलाके को क्यों छोड़ा जा रहा है, यहां भी बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। अगर पीएनजी लाइन पड़ जाए लोगों के लिए काफी आसानी होगी।

एकता नगर निवासी नवीन साहू ने कहा कि पीएनजी लाइन बिछने से लोगों को एलपीजी बुकिंग, गैस खत्म होने और महंगे दाम जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विभाग किन मानकों के आधार पर कालोनियों का चयन कर रहा है। उन्होंने कहा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर आसपास के क्षेत्रों में पीएनजी पहुंच सकती है तो हमारे यहां क्यों नहीं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत और मांग करने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और संबंधित गैस कंपनी से जल्द सर्वे कराकर पीएनजी लाइन बिछाने की मांग की है, ताकि हजारों लोगों को आधुनिक और सुरक्षित गैस सुविधा का लाभ मिल सके।

लखनऊ में मौलाना सैयद काब रशीदी बोले- मदरसों में सुधार की जरूरत, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए भारत का संविधान

सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना सैयद काब रशीदी मदरसों में पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर अभियान चला रहे हैं. मौलाना सैयद काब रशीदी संविधान पर किताब भी लिखी

(जीएनएस)।

लखनऊ : देशभर के मदरसों में पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना सैयद काब रशीदी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि मदरसों में भी सुधार हो, ताकि वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को यह समझ हो सके कि आज की

दुनिया और देश की जरूरतें क्या हैं. उन्होंने कहा, कोशिश है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में भारत के संविधान को शामिल किया जाए, ताकि बच्चों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की जानकारी मिल सके.

मौलाना रशीदी ने बताया, मैंने खुद संविधान की मूलभूत बातों और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को शामिल करते हुए एक किताब लिखी है. यह किताब खास तौर पर मदरसे के छात्रों के लिए तैयार की गई है और जल्द ही इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी. साथ ही इस पुस्तक का पांच भाषाओं में अनुवाद भी कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि मदरसे के छात्र-छात्राएं धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ देश के संविधान की भी शिक्षा हासिल करें, ताकि उन्हें अपने हक, अधिकार और जिम्मेदारियों की सही जानकारी हो सके.

मदरसे के छात्र संविधान की भी शिक्षा हासिल करें.

मौलाना रशीदी ने कहा, सरकार भी मदरसों में सुधार चाहती है, लेकिन सुधार के नाम पर मदरसों की मूलभूत संरचना को बदलना सही नहीं होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि मदरसों का उद्देश्य इंजीनियर या डॉक्टर बनाना नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि ऐसा सिलेबस लागू होना चाहिए जो दीन और दुनिया दोनों के मुताबिक हो, लेकिन मदरसों की बुनियादी पहचान कायम रहनी चाहिए.

उन्होंने दावा किया कि देश के मुस्लिम बच्चों में केवल करीब एक प्रतिशत बच्चे ही मदरसों में शिक्षा लेते हैं, जबकि बाकी 99 प्रतिशत अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं. ऐसे में सरकार को सिर्फ मदरसों पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय बाकी छात्रों की शिक्षा पर भी विचार करना चाहिए.

मौलाना रशीदी ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की कि एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, जो मदरसों के पाठ्यक्रम में जरूरी बदलावों पर काम करे. उन्होंने कहा कि इस अभियान को देशव्यापी रूप दिया जाएगा. इसके तहत असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत कई राज्यों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मदरसों के छात्र-छात्राएं संविधान को समझें, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को जानें और एक जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बनकर

लखनऊ केजीएमयू डॉक्टर दुष्कर्म मामले में डॉ. रमीजुद्दीन को बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

(जीएनएस)।

लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डाक्टर से दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और मतांतरण के दबाव के मामले में आरोपित डॉ. रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है।

सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने मामले को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए आरोपित को राहत नहीं दी जा सकती।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता पैथोलाजी विभाग में प्रशिक्षण ले रही थी। वर्ष 2025 में उसने केजीएमयू प्रशासन को लिखित शिकायत देकर बताया था कि प्रशिक्षण के दौरान उसकी मुलाकात डॉ. रमीजुद्दीन से हुई। आरोप है कि उसने खुद को उत्तराखंड के खटीमा का निवासी और अविवाहित बताकर दोस्ती की।

बाद में शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता गर्भवती हुई तो दवा देकर जबरन गर्भपात करा दिया गया। इसी दौरान उसे पता चला कि आरोपित पहले से शादीशुदा है और उसने अपनी पत्नी का भी मतांतरण कराकर निकाह किया था।

अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपित लगातार पीड़िता पर शादी और मतांतरण का दबाव बनाता रहा। मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। मामले की

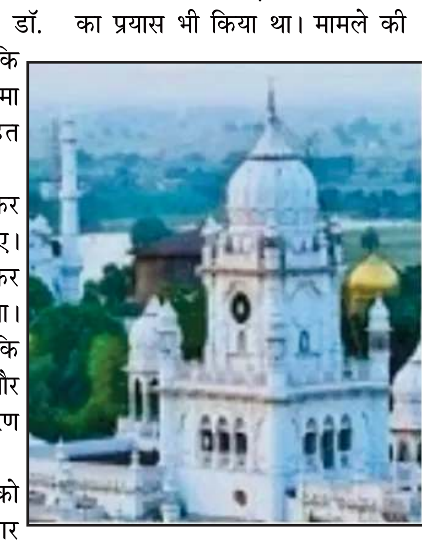

गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

गौरतलब है कि चौक पुलिस ने इस मामले में डॉ. रमीजुद्दीन, उसके माता-पिता और एक सहयोगी के खिलाफ 800 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पुलिस ने दो पीड़िताओं के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों को आरोप पत्र का हिस्सा बनाया है।

आरोपित के कब्जे से बरामद तीन लैपटाप की फारेंसिक जांच में करीब चार टीबी डाटा मिला, जिसमें 500 से अधिक अश्लील वीडियो मिलने का दावा किया गया है। जांच में यह भी सामने आया था कि आरोपित रमीजुद्दीन महिलाओं को सहानुभूति, आर्थिक मदद और करियर में सहयोग का भरोसा देकर करीबियां बढ़ाता था। बाद में संबंध बनाकर वीडियो तैयार करता और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाता था।

पुलिस के मुताबिक, इसी तरीके से दो युवतियों का यौन शोषण, जबरन गर्भपात और मतांतरण कराया गया। चौक पुलिस की जांच में आगरा निवासी एक महिला डाक्टर का मामला भी सामने आया था।

आरोप है कि रमीजुद्दीन ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण कराया और फरवरी 2025 में निकाह किया। विरोध करने पर दो बार गर्भपात कराने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप भी शामिल किए गए हैं। पुलिस ने आरोपित के पिता सलीमुद्दीन, मां खतीजा और निकाह में गवाह बने शारिक खान को भी सहआरोपित बनाया है।